National Action Plan for increasing Milk Production

964. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any National Action Plan for increasing the milk production in the country particularly in the State of Punjab;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total production of milk in the country, State-wise details;

(d) the total demand of milk in the country at present; and

(e) the steps being taken by Government to increase the milk production in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) No, Sir.

(b) Does no arise

(c) State-wise milk production during 1994-95 is given in the enclosed statement. (*See* below)

(d) As per recommended nutritional requirement of 220 grams of milk per head per day the estimated requirement of milk in the country works out to 74.1 million tonnes during 1994-96.

(e) Government of India has been assisting the State/UT Governments under various central/centrally sponsored schemes for strengthening of infrastructure for genetic upgradation of milch animals, feed and fodder development and control and eradiction of diseases.

Statement

Statewise milk production during 1994-95

(000 tone)

State/UT	1994-95 (Prov.)
1	2
1. Andhra Pradesh	4100
2. Arunachal Pradesh	42
3. Assam	697
4. Bihar	3250
5. Goa	31
6. Gujarat	3650
7. Haryana	3950
8. Himachal Pradesh	655
9. Jammu & Kashmir	780
10. Karnataka	3003
11. Kerala	2120
12. Madhya Pradesh	5160
13. Maharashtra	4811
14. Manipur	111
15. Megalaya	54
16. Mizoram	15
17. Nagaland	45
18. Orissa	585
19. Punjab	6400
20. Rajasthan	4850
21. Sikkim	32
22. Tamil Nadu	3963
23. Tripura	38
24. Uttar Pradesh	11321
25. West Bengal	3240
26. A & N Islands	25
27. Chandigarh	39
28. Dadra & N. Haveli	4
29. Daman & Diu	1
30. Delhi	270
31. Lakshadweep	1
32. Pondicherry	29
Total	63272

कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक पूंजी निवेश

965. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में भरपूर क्षमता के अनुसार उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश की यात्रा का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निवेश की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या देश में कृषि क्षेत्र में पूंजी का निवेश उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो यह निवेश के अपेक्षित स्तर से कितने प्रतिशत कम है; और

(ङ) वर्ष 1990-91 और वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितना निवेश किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान: (क) से (ख) कृषि क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए अपेक्षित निवेश आदान-उत्पादन अनुपात, प्रौद्योगिकीय विकास, संभावित वृद्धि दर और विकासात्मक प्रक्रिया में अपनाए गए योजना के माडल आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करना है। यदि किसी एक कारक में

परिवर्तन आता है तो निधियों की आवश्यकता तथा क्षमता में भी परिवर्तन करना पड़ता है। योजना के पूंजीप्रधान मॉडल के अधीन निधियों की आवश्यकता श्रम प्रधान मॉडल से अधिक होगी। आठवीं योजना के दौरान कृषि में जोड़े गए सकल मूल्य में 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने की आश है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में हुआ कुल निवेश वर्ष 1991-92 के मुल्य पर 1,48,800 करोड़ रुपये आंका गया है।

(ङ) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान कृषि में सकल पूंजी निर्माण के लिए किया गया कुल निवेश विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी निर्माण का अनुमान

(करोड़ रू० में)

वर्ष	वर्तमान मूल्य	1980-81 का मूल्य
1990-91	11592	4594
1991-92	13390	4729
1992-93	16617	5371
1993-94	18481	5586
1944-95*	20974	5857

* त्वरित अनुमान

''कपार्ट'' द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड

966. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''कपार्ट'' द्वारा सामाजिक-शैक्षणिक विकास केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर जिलों के विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के व्यापक रूप से प्रसार-प्रचार के लिए सरकार द्वारा किन-किन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच. पटेल): (क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकान

967. श्री रामदेव भंडारी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत एक यूनिट मकान का खर्च कितना है;

(ग) क्या देश के सभी राज्यों में एक यूनिट मकान का खर्च एक जैसा है;

(घ) क्या एक यूनिट के खर्च को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) मैदानी एवं सुगम क्षेत्र में एक यूनिट मकान के लिए खर्च की सीमा इस समय 14,000 रुपए है, जबकि पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में यह 15,800 रुपए है। एक यूनिट मकान के खर्च में स्वच्छ शौचालय, धुंआरहित चूल्हा, ढांचा और सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) एक यूनिट मकान के खर्च को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।